Information of Press Council of Maharashtra

ISSN NO. (Online/E-Journal): 3139-499X | Vol. 1 | Issue 4, October to December 2026

Article 2 | Language: Hindi | Published: October to December 2026

महाराष्ट्र में पत्रकारिता और समाचारपत्र उद्योग का कोविड-पश्चात संकट

Adv. Iliyas Abdulmajeed Khan

ABSTRACT

सारांश

कोविड-19 महामारी का महाराष्ट्र में पत्रकारिता और समाचारपत्र उद्योग पर गहरा तथा दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा है। जनमत निर्माण, लोकतंत्र को बढ़ावा देने और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में समाचारपत्रों की ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्ष 2020 में कोविड-19 का प्रकोप शुरू होने के बाद से मीडिया जगत, विशेषकर प्रिंट पत्रकारिता, अभूतपूर्व आर्थिक और परिचालन संबंधी संकट का सामना कर रहा है।

इस लेख में घटते राजस्व, रोजगार में कटौती, डिजिटल माध्यमों की ओर संक्रमण तथा मीडिया उपभोग के स्वरूप में आए संरचनात्मक बदलावों जैसी प्रमुख चुनौतियों का विश्लेषण किया गया है। साथ ही, महाराष्ट्र में स्वतंत्र पत्रकारिता को टिकाऊ बनाए रखने के लिए सरकार और संबंधित पक्षों द्वारा समन्वित रूप से नीतिगत सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

---

1. प्रस्तावना

महाराष्ट्र में पत्रकारिता और समाचारपत्र उद्योग को कोविड-पश्चात काल में गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। जनमत निर्माण, लोकतंत्र को प्रोत्साहित करने और शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में समाचारपत्रों की भूमिका ऐतिहासिक रूप से महत्त्वपूर्ण रही है। हालांकि, वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से मीडिया जगत, विशेषकर प्रिंट पत्रकारिता, अभूतपूर्व आर्थिक और परिचालन संबंधी संकट से गुजर रहा है। महामारी समाप्त होने के कई वर्ष बाद भी राजस्व में गिरावट, रोजगार का नुकसान और पाठकों की मीडिया संबंधी आदतों में संरचनात्मक बदलाव के कारण यह उद्योग लगातार संघर्ष कर रहा है।

कोविड-19 के शुरुआती लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र के समाचारपत्र उद्योग के कामकाज में अचानक और व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ। कड़े प्रतिबंधों तथा वस्तुओं की सतहों से वायरस के संक्रमण की आशंका के कारण छपे हुए समाचारपत्रों के वितरण पर गंभीर प्रभाव पड़ा। कई शहरों में हाउसिंग सोसायटियों और आवासीय परिसरों ने कुछ समय के लिए समाचारपत्रों की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पूरे राज्य में समाचारपत्रों के प्रसार में उल्लेखनीय

गिरावट आई। प्रतिदिन की नियमित वितरण व्यवस्था पर निर्भर समाचारपत्रों के लिए पाठकों तक पहुँचना कठिन हो गया।

2. विज्ञापन राजस्व में गिरावट और आर्थिक संकट

समाचारपत्र व्यवसाय का प्रमुख आर्थिक आधार विज्ञापन राजस्व भी महामारी के दौरान बुरी तरह प्रभावित हुआ। रियल एस्टेट, खुदरा व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और मनोरंजन सहित विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसाय या तो अस्थायी रूप से बंद हो गए या उन्होंने अपने विपणन और विज्ञापन बजट में भारी कटौती कर दी। क्षेत्रीय समाचारपत्रों को आर्थिक सहारा देने वाले सरकारी विज्ञापनों की संख्या या मात्रा भी कुछ अवधियों में कम हुई अथवा उनके जारी होने में देरी हुई।

इसके परिणामस्वरूप महाराष्ट्र के अनेक छोटे और मध्यम आकार के समाचारपत्रों के लिए अपना कामकाज जारी रखना कठिन हो गया।

विशेष रूप से मराठी, उर्दू और हिंदी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले क्षेत्रीय तथा छोटे समाचारपत्रों के सामने स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई। बड़े राष्ट्रीय मीडिया समूहों की तुलना में इन प्रकाशनों के पास सीमित आर्थिक संसाधन और आरक्षित निधि होती है। विज्ञापन आय में अचानक आई गिरावट के कारण कई प्रकाशकों को समाचारपत्र के पृष्ठों की संख्या घटानी पड़ी, कुछ संस्करण स्थगित करने पड़े अथवा छपाई अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी। कुछ समाचारपत्र स्थायी रूप से बंद हो गए, जिससे स्थानीय पत्रकारिता की कई महत्त्वपूर्ण आवाजें भी लुप्त हो गईं।

3. पत्रकारों और मीडिया कर्मचारियों पर प्रभाव

इस अवधि में पत्रकार भी सबसे अधिक प्रभावित होने वाले वर्गों में शामिल रहे। अनेक संवाददाताओं, छायाकारों और मीडिया कर्मचारियों के वेतन में कटौती हुई, वेतन भुगतान में देरी हुई अथवा उन्हें अपनी नौकरियाँ गंवानी पड़ीं। स्वतंत्र पत्रकार और छोटे शहरों में कार्यरत संवाददाता विशेष रूप से असुरक्षित रहे, क्योंकि उनकी आय अक्सर प्रति समाचार मिलने वाले भुगतान या सीमित मानदेय पर निर्भर करती है। महामारी के दौरान जब घटनास्थल पर जाकर रिपोर्टिंग करना कठिन हो गया और समाचारपत्रों के बजट में कटौती हुई, तब अनेक पत्रकारों ने अपनी आय का प्रमुख स्रोत खो दिया।

इन कठिनाइयों के बावजूद पत्रकारों ने अपना कर्तव्य निभाना जारी रखा। उन्होंने अस्पतालों, क्वारंटीन केंद्रों और दूरदराज के गाँवों से रिपोर्टिंग करके लोगों को वायरस के प्रसार, सरकारी नीतियों और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों के बारे में जानकारी दी। अनेक अवसरों पर महामारी से संबंधित समाचारों का संकलन करते समय पत्रकारों ने अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा को जोखिम में डाला।

दुर्भाग्यवश, पर्याप्त आर्थिक और संस्थागत सहायता के अभाव में अनेक मीडिया पेशेवरों में उपेक्षित होने की भावना पैदा हुई है।

4. डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ता रुझान

कोविड-पश्चात अवधि में डिजिटल मीडिया की ओर तेजी से बढ़ना एक अन्य प्रमुख बदलाव रहा है। लॉकडाउन के दौरान पाठकों ने ताजा समाचारों और तत्काल जानकारी के लिए बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, समाचार वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का रुख किया। इस डिजिटल परिवर्तन ने नए अवसर खोले, लेकिन पारंपरिक समाचारपत्रों के सामने प्रतिस्पर्धा भी बढ़ा दी।

प्रिंट मीडिया की अनेक संस्थाएँ मजबूत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के लिए आवश्यक तकनीकी और आर्थिक निवेश करने हेतु पूरी तरह तैयार नहीं थीं।
महाराष्ट्र के छोटे समाचारपत्रों के लिए आर्थिक सीमाओं और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण डिजिटल प्रकाशन की ओर संक्रमण कठिन रहा है। मोबाइल पर आसानी से पढ़ी जा सकने वाली वेबसाइट विकसित करना, ऑनलाइन सदस्यता व्यवस्था शुरू करना और सोशल मीडिया पर सक्रिय उपस्थिति बनाए रखना—इन सभी के लिए समर्पित कर्मचारियों तथा आवश्यक बुनियादी ढाँचे की जरूरत होती है। पर्याप्त निवेश के अभाव में अनेक समाचारपत्र बड़े डिजिटल मीडिया समूहों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई महसूस करते हैं।

5. उत्पादन लागत में वृद्धि और समाचारपत्रों के अस्तित्व का प्रश्न

हाल के वर्षों में समाचारपत्रों के उत्पादन की लागत में भी वृद्धि हुई है। अखबारी कागज, छपाई की स्याही, परिवहन और अन्य परिचालन खर्चों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। विज्ञापन राजस्व में गिरावट और समाचारपत्रों के प्रसार में कमी के साथ बढ़ती लागत प्रकाशकों पर भारी आर्थिक दबाव डाल रही है।

कुछ मामलों में समाचारपत्रों को अपने आवरण मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी है। इससे उन पाठकों की संख्या और कम होने की आशंका पैदा होती है जो कीमत के प्रति संवेदनशील होते हैं।
इस संकट ने राज्य में स्वतंत्र पत्रकारिता की दीर्घकालिक स्थिरता को लेकर भी गंभीर चिंताएँ पैदा की हैं। स्थानीय समाचारपत्र क्षेत्रीय मुद्दों को सामने लाते हैं, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं और जमीनी स्तर पर कार्यरत लोगों को अपनी बात रखने का मंच प्रदान करते हैं। यदि ये संस्थाएँ कमजोर हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, तो स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सूचना का स्वतंत्र प्रवाह गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

6. सरकारी सहायता और पत्रकार कल्याणकारी नीतियों की आवश्यकता

इस पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के अनेक पत्रकार संगठनों और मीडिया संस्थाओं ने सरकार से अधिक प्रभावी नीतिगत सहायता उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया है।
पत्रकारों के लिए आर्थिक सहायता योजनाएँ, स्वास्थ्य बीमा और आपातकालीन सहायता निधि जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएँ लागू करना एक प्रमुख माँग है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय समुदायों की सेवा करने वाले छोटे समाचारपत्रों को सहायता मिल सके, इसके लिए सरकारी विज्ञापनों का वितरण निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से किए जाने की माँग भी कई मीडिया संगठनों ने की है।

पत्रकारों की सुरक्षा के लिए व्यापक पत्रकार सुरक्षा कानून तथा व्यवस्थित मीडिया कल्याण नीतियों की आवश्यकता पर भी चर्चा बढ़ रही है। ऐसे उपायों से पत्रकार आर्थिक असुरक्षा और बाहरी दबाव से मुक्त होकर अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारियाँ निभा सकेंगे। पत्रकारिता के लिए संस्थागत ढाँचे को मजबूत करने से स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया का संरक्षण होगा, जिसका व्यापक लाभ समाज को मिलेगा।

7. डिजिटल परिवर्तन और भविष्य की दिशा

बदलते परिवेश के अनुरूप मीडिया संस्थानों को भी आवश्यक बदलाव करने होंगे। डिजिटल पत्रकारिता में नवाचार, आय के विभिन्न स्रोत विकसित करना और प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग करना समाचारपत्र उद्योग के अस्तित्व के लिए महत्त्वपूर्ण होगा।

सदस्यता आधारित आय मॉडल, डिजिटल विज्ञापन और मल्टीमीडिया के माध्यम से समाचार प्रस्तुत करने जैसी पहलें समाचारपत्रों को आर्थिक स्थिरता दोबारा प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। साथ ही, इन उपायों से जनहित की सेवा जारी रखना भी संभव होगा।

शैक्षणिक संस्थानों और पत्रकारिता प्रशिक्षण केंद्रों की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। युवा पत्रकारों को डिजिटल कौशल, डेटा पत्रकारिता की तकनीकों और मल्टीमीडिया रिपोर्टिंग की क्षमताओं से लैस करके मीडिया क्षेत्र की अगली पीढ़ी इस उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है।

8. निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी ने महाराष्ट्र में पत्रकारिता और समाचारपत्र उद्योग के स्वरूप को मूल रूप से बदल दिया है। यह क्षेत्र आज भी आर्थिक कठिनाइयों, तकनीकी बदलावों और पाठकों की बदलती आदतों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि, विश्वसनीय पत्रकारिता का महत्त्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है।
यदि सरकारी प्राधिकरण, मीडिया संस्थाएँ, पत्रकार संगठन और नागरिक समाज समन्वित प्रयास करें, तो महाराष्ट्र का समाचारपत्र उद्योग महामारी के बाद उत्पन्न संकट से उबर सकता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निरंतर निभा सकता है।

© 2026 Press Council of Maharashtra. All rights reserved. | Information of Press Council of Maharashtra, Vol. 1 | Issue 4
Downloaded: 27 Oct 2026, 7:06 AM IST